

आर्थिक सुधार

सामान्य आर्थिक सुधार का तात्पर्य आर्थिक प्रक्रियाओं के सुलीकरण है।

* प्रथम चरण के सुधार :- 1991 ई. में आंशिक रूप से सुधार की शूल प्रकृति संरचनात्मक की जिसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था का गतिशील विकास सुनिश्चित करना था। इस क्रम में लक्ष्य आर्थिक लाइसेंसिंग का सुलीकरण कर औद्योगिक विनिमय को आधुनिक बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त उद्योगों में निर्यात निवेश सुनिश्चित करने के प्रयास भी किये गए। आयात पुंजों में कमी तथा पर्यावरण से मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति उद्योगों के सुधारों में प्रमुख महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसे सुधारों के वास्तविक भारत का लक्ष्य आर्थिक क्षेत्र 'लागतान्त्रिक' ही हो पाया।

प्रथम चरण के सुधारों में भारतीय अर्थव्यवस्था को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोलना महत्वपूर्ण था। इससे भारतीय उद्योगों को राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायता मिली। मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ लेने के लिए

विनिवेश तथा निजीकरण जैसी प्रक्रियाओं पर काल्पनिक बल दिया गया था जो वस्तुतः में भी जारी है।

कृषि आकारित अधिवहन को सुदृढ बनाने के उद्देश्य से खल्य खर्च विभिन्न फलों के लिए अनुक्रम समर्पण खल्य (दोई आदी ग्रीहान्त्रिकीय इति) तथा आबिग्रहण खल्य (लडे फिलाने व अग्रपवलयी) के माध्यम से उपास किये गए ।

पूर्वक को कार्यात्मक स्थापना देना भी प्रथम चरण के सुधारों का एक महत्वपूर्ण आचरण था । इसी प्रकार सेवा क्षेत्र तथा आवाहन क्षेत्रों के क्षेत्र में भी किये जाये वाले सुधारों के क्रम में निजी क्षेत्र की प्रसिद्धि के विस्तार पर बल दिया गया था । आवाहन क्षेत्र में विशेषकर लघु रेलवे बंगलाहा तथा इत्यादि में व्यय सुधारा किये गए ।

* द्वितीय चरण के सुधार : - संयन्त्रात्मक सुधारों की निरंतरता बनाये रखने हुए द्वितीय चरण में वित्तीय सुधारों को भी सम्मिलित किया गया था । इसके अन्तर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

(FDI) तथा संविभाजित निवेश (Portfolio ^{Investments} = शेयर निवेश) की वृद्धि पर सर्वाधिक बल दिया गया ।

राष्ट्र के राजकोषीय प्रबंधन को सुदृढ बनाने के लिए

राज्य स्तरीय राजकोषीय सुधार भी किये गए थे ।

~~MTFRP~~ (MTFRP = mid Term Fiscal Reform Programme)

प्रधानमन्त्री राजकोषीय सुधार कार्यक्रम

द्वितीय चरण के सुधारों का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह था कि इनमें

Risk Management
बैंकों में जोखिम प्रबंधन के लिए नई प्रणालियों के विकास पर बल दिया गया था। इन प्रणालियों के माध्यम से बैंकों में फंड स्थानांतरण को सुदृढ़ बनाने का उपाय किया गया।
Fund Transfer

(RTGS: Real Time Gross Settlement)
वास्तविक समय निपटण प्रणाली

** * तृतीय चरण के सुधार - इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य
सम बाजार के सुधारों पर था।

वेदर सम प्रबंधन संबंधी स्थापित कर ऑथोरिटी अनुयायन सुनिश्चित किया जा सके। इसी उद्देश्य से 1926 के सम विधायी में संशोधन भी प्रस्तावित हो उल्लेखनीय है कि तृतीय चरण के सुधारों का उद्देश्य भारत की विधि प्रणाली में लक्षणात्मक परिवर्तन कर लक्षणात्मक सुधारों को संपर्क प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त इसे चरण में शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसी सामाजिक आवश्यकताओं के निर्माण तथा विकास पर भी बल दिया गया है।